क्र० सं०	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	जिले का नाम
7.	मध्य प्रदेश	3	इन्दौर, भोपाल, राजगढ़
8.	महाराष्ट्र	5	थाणे, नागपुर, कोल्हापुर, नासिक, भन्द्रापुर
9.	उड़ीसा	1	कटक
10.	पंजाब	1	भटिण्डा
11.	राजस्थान	1	अजमेर
12.	तमिलनाडु	1	धर्मपुरी
13.	उत्तर प्रदेश	6	मुरादाबाद, साहरनपुर, लखनऊ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मुजफ्फर नगर
14.	पश्चिम बंगाल	5	नाडिया, मुर्शीदाबाद, बांकुरा पुर्लिया, माल्दा
15.	गोवा	2	उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा
	जोड़	39	

Lack of funds in KVIC

2368 . SHRIMATI NIRMALA DESHPANDE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is true that Khadi and Village Industries are suffering because of lack of funds; and

(b) whether it is resulting in loss of employment in the rural sector?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) No, Sir.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

लम्बित औद्योगिक परियोजनाएं

2369. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अद्यतन स्थिति के अनुसार कुछ राज्यों की औद्योगिक परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित ऐसी परियोनजाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की कुल लागत क्या है और क्या असाधारण विलम्ब के कारण इनकी लागत में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजनाओं को स्वीकृति देने में हुए विलम्ब के कारणों का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ङ) 31.10.1998 की स्थिति के अनुसार कुछ राज्यों के संबंध में वस्त्र, विस्फोटक आदि के विनिर्माण के लिए कुल 63 औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पर सरकर ने अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। इन प्रस्तावों में लगभग 221.73 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदनों की प्राप्ति, उन पर विचार तथा उनका निपटान करना एक सतत प्रक्रिया है तथा आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए सभी कदम उठाए जाते हैं। आवेदनों का वास्तविक निपटान, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनाई गई क्षेत्रीय नीति, विशिष्ट मामलों में उनकी सिफारिशों पर आवेदक द्वारा संगत सूचना देने पर भी निर्भर करता है।